

Notes by Akhilesh Kumar (G T Assit. Professor)

J K College Biraul Darbhanga

YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAU, DARBHANGA

For – LNMU B. Com part -1 , Subsidiary PAPER -I ,Business Economics and Environment Unit- 5 Business Environment



Meaning of Fiscal Policy राजकोषीय नीति का अर्थ

राजकोषीय नीति का सम्बन्ध सरकार के आय-व्यय ऋण तथा बजट नीति से होता है ।

Easy to Understand the concept

- इसमें सरकार यह निश्चित करती है की विभिन्न वस्तुओ पर किस दर से कर लगाया जाए तथा इन करो से प्राप्त राशि को किन-किन मदों पर व्यय किया जाए ?
- सार्वजनिक व्यय यदि आय से अधिक है तो इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाए ?
- बजट के घाटे की पूर्ति ऋण लेकर की जाए अथवा नए नोटों का निर्गमन किया जाए ।

अतः स्पष्ट है की राजकोषीय नीति से आशय सरकारी व्यय करारोपण ऋण की प्राप्ति एवं व्यवस्था से होता है । वर्तमान में राजकोषीय नीति को आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है ।

आर्थर स्मिथीज के अनुसार, “राजकोषीय नीति वह है जिसके अन्तर्गत सरकार अपने व्यय तथा आगम का प्रयोग इस प्रकार करती है की राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इसका वछ्नीय प्रभाव पड़े तथा अवांछनीय प्रभाव को रोका जा सके ।”

विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं—

- 1. आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना—** एक विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना होता है। सरकार को अपनी आय व्यय एवं ऋण नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे देश में बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन मिले तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। सरकार उधमियो को करो में छुट एव सहायता देकर विनियोग के लिये प्रोत्साहित कर सकती है। सरकारी व्यय ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जिससे आधारभूत अवसंरचना का विकास हो सके तथा उत्पादन एव आर्थिक विकास को गति मिल सके।
- 2. आय एव सम्पत्ति के वितरण की विषमताओं को कम करना—** देश में आय व सम्पत्ति के वितरण में असमानता होने पर सरकार धनी व्यक्तियों से प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से धन एकत्रित करके निर्धन वर्ग पर व्यय करती है जिससे सामाजिक न्याय होता है तथा आर्थिक विकास भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आजकल सरकार निर्धन वर्ग को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क चिकित्सा, वर्द्धावस्था पेन्शन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को कम मूल्य पर

खाद्य सामग्री वितरित करके सामाजिक न्याय की स्थापना करती है ।

3. **संसाधनों का उचित आबंटन**— राजकोषीय नीति की सहायता से साधनों का विलासितापूर्ण कार्यों से आवश्यक कार्यों की ओर हस्तांतरण किया जा सकता है । विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर उँची दरों से कर लगाकर तथा अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को करों में छूट प्रदान करके साधनों का न्यायोचित तथा अनुकूलतम वितरण किया जा सकता है । अतः राजकोषीय नीति के माध्यम से सिमित प्राकृतिक साधनों का प्राथमिकताओं के आधार पर प्रयोग सम्भव हो जाता है।
4. **पूँजी निर्माण में वृद्धि**— अल्प विकसित देशों में निम्न आय स्तर होने के कारण बचत व विनियोग कम होते हैं । फलतः पूँजी निर्माण कम हो पाता है । एक उपयुक्त राजकोषीय नीति के माध्यम से पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है । राजकोषीय नीति में कर नीति के माध्यम से उपभोग को कम करके बचतों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे देश में पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है
5. **आर्थिक स्थिरता**— अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मन्दी की स्थिति को नियन्त्रित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है । मुद्रा स्फीति के समय सरकार जनता पर अतिरिक्त कर लगाकर उनसे बढ़ी हुई क्रय शक्ति को निष्क्रिय

कर देती है तथा दूसरी तरफ उत्पादकों को करो में छुट देकर उत्पादन वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करती है। इससे माँग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित होने से बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार मन्दी की स्थिति में सरकार व्यय में वर्धि करके अधिक क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कर सकती है।

6. **रोजगार अवसरों में वर्धि**— रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करना भी राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। सरकार उचित कर नीति सावर्जनिक व्यय एवं सावर्जनिक ऋण के द्वारा रोजगार में वृद्धि कर सकती है। सावर्जनिक क्षेत्र में बड़े तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना करके लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

7. **संसाधनों का उचित आबंटन**— राजकोषीय नीति की सहायता से साधनों का विलासितापूर्ण कार्यों से आवश्यक कार्यों की ओर हस्तांतरण किया जा सकता है। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर ऊँची दरों से कर लगाकर तथा अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को करो में छुट प्रदान करके साधनों का न्यायोचित तथा अनुकूलतम वितरण किया जा सकता है। अतः राजकोषीय नीति के माध्यम से सिमित प्राकृतिक साधनों का प्राथमिकताओं के आधार पर प्रयोग सम्भव हो जाता है।

8. **पूँजी निर्माण में वृद्धि**— अल्पविकसित देशों में निम्न आय स्तर होने के कारण बचत व विनियोग कम होते हैं। फलतः पूँजी निर्माण कम हो पाता है। एक उपयुक्त राजकोषीय नीति के माध्यम से पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। राजकोषीय नीति में कर नीति के माध्यम से उपभोग को कम करके बचतों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे देश में पूँजी निर्माण में वृद्धि
9. **आर्थिक स्थिरता**— अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मन्दी की स्थिति को नियन्त्रित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। मुद्रा स्फीति क्र समय सरकार जनता पर अतिरिक्त कर लगाकर उनसे बढ़ी हुई क्रय शक्ति को निष्क्रिय कर देती है तथा दूसरी तरफ उत्पादकों को करों में छुट देकर उत्पादन वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करती है। इससे माँग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित होने से बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार मन्दी की स्थिति में सरकार व्यय में वृद्धि करके अधिक क्रयशक्ति अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कर सकती है।
10. **रोजगार अवसरों में वृद्धि**— रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करना भी राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। सरकार उचित कर नीति सावर्जनिक व्यय एवं सावर्जनिक ऋण के द्वारा रोजगार में वृद्धि कर सकती है। सावर्जनिक क्षेत्र में बड़े तथा आधारभूत उद्योगों की

Notes by Akhilesh Kumar (G T Assit. Professor)

J K College Biraul Darbhanga

YouTube : A commerce Education

स्थापना करके लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।